कानपुर, बुधवार, 18 फरवरी, 2026
वर्षः 03, अंकः 47, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड महाराष्ट्र में मुस्लिमों का 5% आरक्षण रद्द...>Pg12

केडीए ने 21 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग की ध्वस्त...>Pg03

मूल्यः 2 ₹

एक जिला एक उत्पाद योजना में महाघोटाला

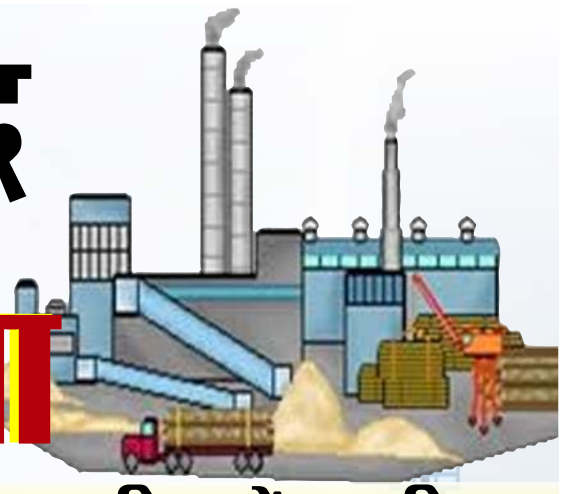

9-10 करोड़ की निकासी संदिग्ध, प्रदेश भर से मांगा गया 7 दिन में पूरा हिसाब

खबरः एक नजर में

- ओडीओपी योजना की मार्जिन मनी सब्सिडी में करोड़ों के घोटाले के संकेत
- बैंक ऑडिट में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता उजागर
- 2022-23 की सब्सिडी फाइलों की प्रदेशव्यापी जांच शुरू
- कई इकाइयों को बिना भौतिक सत्यापन सब्सिडी जारी
- कानपुर देहात की इकाइयों के मामले सबसे ज्यादा संदिग्ध
- दादानगर समेत कई शाखाओं से 9-10 करोड़ की निकासी का उल्लेख
- उद्योग निदेशालय ने 7 दिन में पूरा वित्तीय ब्योरा तलब किया
- संयुक्त सर्वे और ऑन-साइट सत्यापन अब अनिवार्य
- संबंधित बैंक अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में
- जरूरत पड़ने पर अपराध शाखा/केंद्रीय एजेंसी से जांच संभव
- पुराने लाभार्थियों की भी दोबारा जांच के आदेश

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर। सूक्ष्म व लघु उद्योगों को सहारा देने वाली ÷एक ज़िला एक उत्पाद÷ योजना अब बड़े घोटाले के आरोपों में घिर गई है। मार्जिन मनी सब्सिडी वितरण में भारी अनियमितता उजागर होने के बाद उद्योग विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। बैंक ऑडिट में करोड़ों रुपये की संदिग्ध निकासी सामने आने पर कई शाखाएं जांच के घेरे में हैं। आरोप है कि पात्रता जांच और भौतिक सत्यापन के बिना ही सब्सिडी जारी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया।

मामले के सामने आते ही उद्योग विभाग में हड़कंप मच गया है। उद्योग निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्त उद्योग को कड़े निर्देश जारी करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में वितरित सब्सिडी का पूरा वित्तीय और भौतिक ब्योरा सात दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि सत्यापन में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित बैंक शाखा और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

प्राथमिक जांच और बैंक स्तर पर कराए गए विशेष ऑडिट में खुलासा हुआ है कि कई इकाइयों को नियम विरुद्ध तरीके से सब्सिडी जारी की गई। दस्तावेज अधूरे पाए गए, कई

जगह इकाइयों का वास्तविक संचालन संदिग्ध मिला, जबकि कुछ मामलों में भौतिक अस्तित्व तक स्पष्ट नहीं है। इसके बावजूद खातों में सब्सिडी की रकम ट्रांसफर कर दी गई।

सबसे अधिक संदिग्ध प्रकरण कानपुर देहात क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों से जुड़े बताए जा रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट में दादानगर सहित कई शाखाओं के खातों से लगभग 9 से 10 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी निकाले जाने का उल्लेख है। सूत्रों का दावा है कि शाखा स्तर पर आपसी समन्वय से फाइलें आगे बढ़ाई गईं और पात्रता की शर्तों को नजरअंदाज किया गया।

जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त अंजनीश प्रताप सिंह ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब किसी भी इकाई को सब्सिडी तभी दी जाएगी जब बैंक और उद्योग विभाग की संयुक्त टीम

- बैंक ऑडिट में हुआ खुलासा, सत्यापन किए बिना बांट दी गई सब्सिडी
- मार्जिन मनी सब्सिडी में करोड़ों की सेंधमारी, अफसरों व बैंक के गठजोड़ की आशंका

मौके पर जाकर सर्वे करेगी और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट देगी। बिना संयुक्त निरीक्षण के कोई भुगतान नहीं होगा। पुराने मामलों की भी पुनः जांच कराई जाएगी।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार घोटाले की वास्तविक रकम का आकलन अभी जारी है। यदि जांच में वित्तीय गड़बड़ी का दायरा बढ़ता है तो मामले की जांच अपराध शाखा या केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जा सकती है। विभागीय स्तर पर संबंधित फाइलें, स्वीकृति पत्र, निरीक्षण रिपोर्ट और बैंक लेनदेन का मिलान शुरू कर दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह योजना की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल होगा, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य स्थानीय उत्पाद और छोटे उद्यमियों को आर्थिक सहारा देना है, न कि कागजी इकाइयों के जरिए सरकारी धन निकालना।

मायावती ने विपक्षी दलों पर भ्रामक प्रचार का आरोप लगाया

2027 चुनाव: बसपा अकेले दम पर लड़ेगी, नहीं होगा गठबंधन

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तेज होती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच मायावती ने गठबंधन की संभावनाओं पर साफ और कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि बहुजन समाज पार्टी आगामी चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने गठबंधन से जुड़ी चर्चाओं और खबरों को सुनियोजित राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश बताया और कहा कि पार्टी बहुमत के लक्ष्य के साथ स्वतंत्र रणनीति पर आगे बढ़ रही है।

दिल्ली स्थित अपने टाइप-8 सरकारी बंगले पर मीडिया में उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने सफाई दी और इसे सुरक्षा जरूरतों से जुड़ा निर्णय बताया। मायावती ने कहा कि विरोधी दल मुद्दों के अभाव में अनावश्यक

- सुरक्षा मानकों के तहत मिला दिल्ली का टाइप-8 बंगला
- बोलीं, इसे मुद्दा बनाकर किया जा रहा राजनीतिक शोर

विवाद खड़े कर रहे हैं ताकि बसपा की राजनीतिक दिशा और अभियान को प्रभावित किया जा सके।

मायावती ने कहा कि सोशल मीडिया और कुछ मंचों पर बसपा के संभावित गठबंधन को लेकर चलाई जा रही खबरें पूरी तरह निराधार हैं। उनका आरोप है कि यह सब बसपा के कोर वोटर और कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा करने की रणनीति का हिस्सा है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि पूर्व के चुनावी

अनुभवों ने पार्टी को यह सिखाया है कि गठबंधन की राजनीति में बसपा को अपेक्षित राजनीतिक लाभ नहीं मिला। बसपा का वोट तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन सहयोगी दलों का वोट पार्टी प्रत्याशियों तक नहीं पहुंचा, जिससे संगठन को नुकसान उठाना पड़ा।

मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां आंबेडकरवादी सामाजिक न्याय की सोच से मेल नहीं खातीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे ÷हाथी की मस्त चाल÷ के साथ मिशन 2027 की तैयारी में जुटे रहें और किसी भी भ्रामक प्रचार से प्रभावित न हों।

दिल्ली में आवंटित टाइप-8 बंगले को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि यह आवंटन पूरी तरह सुरक्षा एजेंसियों के मानकों के आधार पर किया गया है। पहले भी सुरक्षा कारणों से कई आवंटन हुए, जिन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया या बाद में छोड़ दिया। इस बार सुरक्षा व्यवस्था के अनुरूप होने के कारण आवंटन लिया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, बसपा को घेरने और उसकी छवि को प्रभावित करने के प्रयास और तेज होंगे। ऐसे में भीमराव आंबेडकर की विचारधारा से जुड़े समर्थकों और पार्टी कैडर

हाईलाइट्स

- बसपा 2027 विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के मूड में
- मायावती ने गठबंधन की सभी अटकलों को बताया फर्जी
- विपक्षी दलों पर सुनियोजित भ्रम फैलाने का आरोप
- पिछले गठबंधनों से राजनीतिक नुकसान का दावा
- सपा, कांग्रेस, भाजपा की नीतियों पर वैचारिक असहमति जताई
- दिल्ली टाइप-8 बंगले का आवंटन सुरक्षा आधार पर बताया
- कार्यकर्ताओं को मिशन 2027 के लिए सक्रिय रहने का आह्वान
- चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक हमले बढ़ने की जताई आशंका

को राजनीतिक रूप से सतर्क और संगठित रहने की जरूरत है।

फर्जी रजिस्ट्री मामले में गुमराह कर रहे बिल्हौर सब-रजिस्ट्रार

» मुंबई में बसे बकोठी गांव के लोगों की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री हो गई

» स्टांप एवं निबंधन विभाग की महानिदेशक नेहा शर्मा ने मांगा जवाब तो दिए जा रहे गोलमोल तर्क

» बिल्हौर तहसील में नियम कायदों की धज्जियां उडाकर फर्जी रजिस्ट्री और एग्रीमेंट से हडपी जा रही जमीनें

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

तहसील - बिल्हौर जनपद - कानपुर नगर

स्वराज इंडिया एक्सक्लूसिव

बड़ा भू-घोटाला बेनकाब

मुंबई में बैठे चाचा की जमीन बिल्हौर में भतीजे ने बेच दी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्व विभाग के भू-माफिया विरोधी दावों की पोल खोलता एक सनसनीखेज मामला कानपुर जिले की तहसील बिल्हौर से सामने आया है। यहां ग्राम बकोठी में 40-45 वर्षों से मुंबई में रह रहे एक व्यक्ति की जमीन को फर्जी विक्रेता खड़ा कर रजिस्ट्री करा दी गई। हैरानी की बात यह है कि यह सब गवाहों, वकीलों, बायोमेट्रिक पहचान और रजिस्ट्री कार्यालय की मौजूदगी में हुआ और किसी को भनक तक नहीं लगी।

सूत्रों के अनुसार मामला संक्रमणीय भूमिधरी की आराजी गाटा संख्या 486 (0.1950 हे.) और 488 (0.1750 हे.), कुल 0.3700 हेक्टेयर भूमि से जुड़ा है। दस्तावेजों में इस जमीन की रजिस्ट्री 30 जुलाई 2025 को दर्शाई गई है, जिसमें विक्रेता के रूप में कल्याणदत्त व नारायणदत्त (पुत्र ओंकारनाथ) के नाम दर्ज हैं। जबकि ग्रामीणों और ग्राम प्रधान का साफ कहना है कि असल मालिक बीते चार दशक से मुंबई में रेलवे सेवा में कार्यरत है और गांव से उनका कोई सीधा संपर्क नहीं रहा।

चोर पर मोर! ब्लैकमेलिंग का नया खेल

मामले में नया मोड़ तब आया जब गांव के ही कुछ दबंगों अकुल शर्मा और सुमित शर्मा को इस फर्जीवाड़े की जानकारी हुई। आरोप है कि उन्होंने पोल खोलने की धमकी देकर क्रेता पक्ष पर दबाव बनाया और विवाद निपटाने के नाम पर अपनी माता श्रीमती कमला देवी के पक्ष में एक स्टांप पेपर पर लिखापढ़ी करा ली, ताकि भविष्य में जमीन बेचने पर मुनाफे में हिस्सा मिल सके। क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने जिलाधिकारी कानपुर नगर से इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच, दोषियों पर एफआईआर, और फर्जी रजिस्ट्री को तत्काल निरस्त करने की मांग की है, ताकि भू-माफिया नेटवर्क पर प्रभावी लगाम लग सके। ग्रामीणों का आरोप है कि इस पूरे खेल में स्थानीय वकीलों और दलालों का संगठित नेटवर्क सक्रिय रहा। बिना असली मालिक की मौजूदगी के दस्तावेज पूरे कराए गए और नियमों को कागजों में ही पूरा दिखा दिया गया। सबसे बड़ा सवाल है कि बायोमेट्रिक सिस्टम होते हुए फर्जी फिंगरप्रिंट कैसे मान्य हुए? क्या रजिस्ट्री कार्यालय के भीतर मिलीभगत के बिना यह संभव है?।

⇨ 40 साल पहले मुंबई में बसे मालिक के नाम पर रची गई रजिस्ट्री की साजिश

⇨ सरकारी तंत्र को ठेंगा दिखाते हुए फर्जी कागजों से बेच दी गई दूसरे की जमीन

गुमनामी बनी हथियार, जालसाजों ने खेला खेल

इसी दूरी और गुमनामी का फायदा उठाकर भू-माफियाओं ने फर्जी व्यक्तियों को असली मालिक बताकर पेश किया और जमीन की रजिस्ट्री करा दी। सवाल यह है कि जब रजिस्ट्री में वास्तविक व्यक्ति की उपस्थिति, पहचान और फिंगरप्रिंट अनिवार्य है, तो फर्जी लोगों की पहचान कैसे स्वीकार कर ली गई?।

विक्रेता के नाम के आगे लिखा क्रेता के पति का मोबाइल नंबर

जमीन क्रेता का पति ही बना है गवाह

कानपुर। बिल्हौर तहसील में तैनात सब रजिस्ट्रार इरशाद अहमद और सिंडीकेट की मिलीभगत से फर्जी व्यक्ति दिखाकर रजिस्ट्री और एग्रीमेंट कर बडे पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। अब तक यहां आधा दर्जन से अधिक फर्जी रजिस्ट्री-एग्रीमेंट प्रकरण सामने आए हैं। जिनमें नियम कायदों की अनदेखी करके करोडों रूप्यों की जमीन का घालमेल कर दिया गया। सब रजिस्ट्रार ने एक बार ऐसे प्रकरणों में चेक करने की कोशिश नहीं की, उल्टा गलत को सही साबित करने में जुटे हुए हैं।

FOLLOW UP

स्वराज इंडिया समाचार पत्र को बकोठी गांव में कृषि जमीन की एक रजिस्ट्री पहुंचाई गई। जिसके मालिकान मुंबई में करीब 40 साल पूर्व चले गए और आजतक नहीं आए। इस बात की तस्दीक स्थानीय ग्रामीण भी करते हैं। बिल्हौर रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रष्टाचार और सांठगांठ करके उनके परिवारिक भतीजे रोहित शर्मा ने अन्य व्यक्ति को खडा करके

बिल्हौर तहसील के सब रजिस्टार इरशाद अहमद

उनकी कृषि जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम करा ली। सब रजिस्ट्रार इरशाद की भूमिका इस लिए भी संदिग्ध हो गई कि बिना आधार, पैन कार्ड के सत्यापन के ही रजिस्ट्री कैसे कर दी गई। जब कि विक्रेता के खाते में कोई ट्रांजैक्शन का जिक्र नहीं है। अब जब इस मामले में बिल्हौर के रजिस्ट्रार इरशाद से बात की गई तो वह बडे आराम से कहते हैं कि उनके आधार कार्ड देखे गए थे लेकिन अगर वह फर्जी थे तो हम कैसे जानें कि फर्जी हैं। अब उनके इस तर्क से तो कोई भी किसी की जमीन मकान की रजिस्ट्री करा लेगा।

जब कि रजिस्ट्री के समय विक्रेता-केता का पेन कार्ड, आधार कार्ड और खाते में धनराशि का ट्रांजेक्शन चेक करना प्राथमिक कार्य हैं लेकिन इसकी अनदेखी की गई। स्वराज इंडिया संवाददता द्वारा जब कृषि जमीन रजिस्ट्री की पडताल की कई चैकाने वाले तथ्य सामने आए। विक्रेता कल्याण दत्त के नाम के आगे जो मोबाइल 9936686221 नंबर दर्ज है उसपर कॉल की गई तो फोन रोहित शर्मा नाम के व्यक्ति उठाता है जो कि केतनी का पति है जब कल्याण दत्त के बारे में पूछा जा रहा है तो बताया कि वह यहां नहीं है, कहा कि उनका मोबाइल बंद है दो तीन में बात करा दूंगा, रिपोर्टर ने 5 दिन बाद फिर फोन किया तो रोहित शर्मा ने टहलाने का प्रयास कर इधर उधर की बातें की। जब उनका मुंबई का पता पूछा गया तो वह भी नहीं बता सका। वहीं, ग्रामीणों ने बताया कि रोहित, कल्याण दत्त का भतीजा है। उसी ने पूरे खेल का अंजाम दिया है। वहीं, रजिस्ट्री के पृष्ठ संख्या 5 में गवाही के तौर पर भी रोहित का ही नाम दर्ज है। जब कि केता कामिनी, रोहित की पत्नी है। वहीं, एक गवाह में उपेंद्र पुत्र प्रदीप निवासी बकोठी का नाम दर्ज है, जब उसके मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उसने बताया कि हमे ज्यादा जानकारी नहीं है, रोहित हमको ले गए थे, पैसे का लेनदेन भी मेरे सामने नहीं हुआ है। गवाह ने अपनी उम्र करीब 32 साल बताई जब कि कल्याण दत्त और नारायन दत्त करीब 40 साल पहले गांव से चले गए थे तो सबसे बडा सवाल यह है कि उसने उनकी शिनाख्त कैसे की जब वह पैदा भी नहीं हुआ था।

स्वराज इंडिया | कानपुर सिटी | 03

बिल्हौर तहसील क्षेत्र में नियम कायदों की धज्जियां उडाकर हड़पी जा रही जमीनें

फर्जीवाड़े से अनजान बने बैठे हैं बिल्हौर तहसील के रजिस्ट्रार

स्वराज इंडिया खुलासा

बड़ा भू-घोटाला बेनकाब

मुंबई में बैठे चाचा की जमीन बिल्हौर में भतीजे ने बेच दी

स्वराज इंडिया ने खोली भ्रष्टाचार की परतें

एआईजी स्टांप श्याम सिंह का चहेता है सब रजिस्ट्रार

कानपुर की तत्कालीन एवं वर्तमान में उप्र स्टांप एवं निबंधन विभाग की महानिदेशक नेहा शर्मा तक प्रकरण पहुंचा तो उन्होने एआईजी स्टांप श्याम सिंह बिसेन से दो दिन में रिपोर्ट भेजने को कहा लेकिन मामले को हल्का करने के लिए तथ्यों को घुमा फिराकर बताने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, सूत्रों का दावा है कि बिल्हौर का सबरजिस्ट्रार इरशाद एआईजी स्टांप श्याम सिंह बिसेन का चहेता है, उसको ही उन्होने तैनाती दिलाई थी। इरशाद करीब 3 साल से बिल्हौर में तैनात हैं, उनकी शिकायतों को एआइजी स्टांप ही मैनेज कर लेते हैं। इस वजह से बडे बडे मामलों में कुछ नहीं हुआ। वहीं, विभाग के ही विशेष सचिव सुधीर कुमार ने बताया कि मामला डीजी मैडम के संज्ञान में है, रिपोर्ट मांगी गई है। दोषी और बचाने वालों पर भी कार्रवाई होगी।

मीडिया का फोन नहीं उठा रहे एआईजी स्टांप

बकोठी गांव की फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण को लेकर स्वराज इंडिया ने खुलासा किया तो हडकंप मच गया। इस मामले के अपडेट को लेकर एआईजी स्टांप कानपुर श्याम सिंह बिसेन से संवाददता ने फोन पर संपर्क किया तो पहले तो कहते रहे कि रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद ही बताया जा सकता है कि लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई न ही सही जानकारी दी जा रही है। श्याम सिंह मीडिया कर्मियों का फोन भी नहीं उठा रहे हैं। वहीं, बताया जा रहा है कि फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले रोहित शर्मा ने कुछ इलाके के के कुछ प्रापर्टी डीलरों से संपर्क किया है, वह जमीन की बिक्रीकर रकम हडपने की फिराक में है।

विशेष कार्याधिकारी एवं उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह की बड़ी कार्रवाई

केडीए का बुलडोजर एक्शन

21 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। अवैध प्लाटिंग और बिना स्वीकृत निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने बुधवार सुबह बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए करीब 21 बीघा क्षेत्र में विकसित अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन-1बी की टीम ने की।

अभियान का नेतृत्व विशेष कार्याधिकारी एवं उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने किया। कार्रवाई के दौरान तीन जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध रूप से विकसित सड़कों, नालियों, बाउंड्रीवाल, बिजली के खंभों, पिलरों तथा निर्मित व निर्माणाधीन भवनों को तोड़कर साफ कर दिया गया।

प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक संबंधित भूखंडों पर बिना लेआउट स्वीकृति और बिना अनुमति प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जो नियमों के विपरीत है। कार्रवाई के समय अवर अभियंता हिमांशु बर्नवाल, प्रवर्तन स्टाफ तथा पुलिस बल मौजूद रहा, जिससे अभियान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराया गया।

➪ तीन जेसीबी लगाकर सड़क, नाली, बाउंड्रीवाल और निर्माणाधीन ढांचे तोड़े गए

अधिकारियों ने बताया कि सिंहपुर और गंगपुर चकबदा क्षेत्र में लगभग 8 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और वहां भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।

- केडीए ने लगभग 21 बीघा में अवैध प्लाटिंग पर की बड़ी कार्रवाई
- प्रवर्तन जोन-1बी की टीम ने चलाया संयुक्त अभियान
- तीन जेसीबी से सड़क, नाली, बाउंड्रीवाल और ढांचे ध्वस्त
- बिना लेआउट स्वीकृति विकसित हो रही थी प्लाटिंग
- प्रवर्तन टीम के साथ पुलिस बल भी रहा मौजूद
- सिंहपुर और गंगपुर चकबदा में भी अगली कार्रवाई तय
- जमीन खरीद से पहले स्वीकृति जांचने की अपील

प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन खरीदने से पहले प्लाटिंग की वैधता और स्वीकृति की जानकारी अवश्य कर लें तथा मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य कराएं, जिससे भविष्य में किसी प्रकार के आर्थिक या कानूनी नुकसान से बचा जा सके।

डॉ. रवि प्रताप सिंह, विशेष कार्याधिकारी, उपजिलाधिकारी

सेंट्रल स्टेशन पर बंद सुरंग पैदल यात्रियों के लिए खुलेगी

मेट्रो कार्य की वजह से सुतरखाना मार्ग था प्रभावित, राहगीरों को मिलेगी राहत

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। मेट्रो निर्माण कार्य के कारण खराब हुई सड़कों और लंबे समय से बंद पड़ी प्लेटफार्म सुरंग की समस्या से जूझ रहे राहगीरों को आखिरकार बड़ी राहत मिलने जा रही है। सुतरखाना साइड से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सुरंग को पैदल यात्रियों के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है। सुरंग बंद होने से दिव्यांगजन, बुजुर्ग और दैनिक आवाजाही करने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

स्थानीय नागरिकों ने समस्या को गंभीर बताते हुए आर्यनगर क्षेत्र के विधायक अमिताभ बाजपेई से शिकायत की। मामले को संज्ञान में लेते हुए विधायक ने तत्काल अधिकारियों से वार्ता के निर्देश दिए। इसके बाद पार्षद रजत बाजपेई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराया।

प्रतिनिधिमंडल ने सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट (सीटीएम) अधिकारी आशुतोष सिंह से विस्तृत वार्ता की और पैदल यात्रियों, दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों को हो रही परेशानी को प्रमुखता से रखा। वार्ता के दौरान विधायक से चर्चा के बाद सीटीएम ने सुरंग को पैदल आवागमन के लिए खोलने के निर्देश जारी कर दिए। प्रतिनिधिमंडल में पार्षद रजत बाजपेई के साथ पप्पन शर्मा, अंबर त्रिवेदी (पूर्व पार्षद), पवन गुप्ता, अनुज निगम सहित कई स्थानीय नागरिक शामिल रहे। निर्णय की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय लोगों ने राहत जताई और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। सुरंग खुलने के बाद स्टेशन तक पहुंचने वाले पैदल यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी और सड़क मार्ग पर भीड़ का दबाव भी कम होगा।

सुतरखाना क्षेत्र से होकर स्टेशन जाने वाले रास्ते को खोलने की मांग को लेकर कुछ लोग आए थे, जिन्होंने ज्ञापन दिया हैं। सभी पहलुओं को देखकर निर्णय लिया जाएगा

आशुतोष सिंह, सीटीएम कानपुर सेंट्रल

बोर्ड परीक्षा: जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा

केंद्र व्यवस्थापकों को शांतिपूर्ण संचालन के निर्देश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बुधवार को बोर्ड परीक्षा की प्रथम पाली (हिंदी) के दृष्टिगत कैलाश नाथ बालिका इंटर कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम, स्ट्रांग रूम तथा विभिन्न परीक्षा कक्षों का गहन अवलोकन किया। मौके पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक व अन्य कर्मचारी उपस्थित मिले।

जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो गई हैं। कानपुर नगर जनपद में कुल 124 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रथम पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण व सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो रही है।उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और परीक्षा संचालन से जुड़े सभी मानकों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित व अनुकूल वातावरण मिल सके।जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की कि परीक्षाओं के दौरान धार्मिक स्थलों, मैरिज लॉन व अन्य स्थानों पर लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित सीमा में रखें। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

हंटर सेना की सदस्य थी तबस्सुम, 2.75 करोड़ की कर चोरी में पुलिस ने दबोचा

10वीं फेल है शातिर तबस्सुम, करती थी फ्राड

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कानपुर की तबस्सुम ने अपने रिश्तेदारों और साथियों के साथ मिलकर बोगस फर्मों के जरिए 2.75 करोड़ की कर चोरी की। लखनऊ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से फर्जी दस्तावेज और बैंक कार्ड बरामद किए हैं। कानपुर में बोगस फर्म बनाकर 2.75 करोड़ की कर चोरी के मामले में लखनऊ क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ी तबस्सुम डब्ल्यू-वन साकेतनगर की रहने वाली है। उसे और उसके तीन साथियों को लखनऊ की साइबर सेल, सर्विलांस टीम और लखनऊ इटौंजा पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ पुलिस की पूछताछ में तबस्सुम ने बताया है कि वह कंजड़नपुरवा के पास साकेतनगर में रहती है।हालांकि, उसने पुलिस को जिस घर का पता दिया है वह उसमें किराये पर रहती थी और करीब पांच साल पहले उसको छोड़कर दूसरी जगह रहने लगी थी। उस मकान के पास रहने वाली महिला ने पहचान छिपाने की शर्त पर बताया कि तबस्सुम उर्फ जाह्नवी

मकान की पहली पहली मंजिल पर सपरिवार रहती थी। लाल रंग की बुलेट से चलने वाला उसका पति क्या काम करता था किसी को नहीं पता।

दोनों बेटों की सफलता में पढ़ाई रोड़ा नहीं बन पाएगी

उसके दोनों बच्चे करन-अर्जुन केशवनगर स्थित इंटर कॉलेज के छात्र थे। वह खुद 10वीं फेल थी, लेकिन कहती थी कि दोनों बेटों की सफलता में पढ़ाई रोड़ा नहीं बन पाएगी। कई साल तक वहां रहने के बाद वह मकान खाली कर इलाके के दूसरे अपार्टमेंट में रहने चली गई थी। अगले दो-तीन साल तो वहां रही हालांकि वह फिर कहां चली गई इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता।

ये था पूरा मामला

तबस्सुम अपनी बड़ी बहन गुलशन के दामाद अम्मार अंसारी के कहने पर बोगस फर्मों के माध्यम से टैक्स चोरी के खेल में शामिल हुई थी। उसका काम दस्तावेज उपलब्ध कराना और बिल बनवाना था। इस खेल में उसकी मदद प्रशांत बेंजवाल करता था जो कि पहले कानपुर के एक शॉपिंग मॉल में कैशियर था।

बैंक किट और अन्य दस्तावेज बरामद

जल्दी अमीर बनने के लालच में नौकरी छोड़कर वर्ष 2023 में लखनऊ रहने चला गया था। प्रशांत फर्म रजिस्ट्रेशन के बाद बोगस आईटीसी को अन्य फर्म को बेचकर फर्जी बिल और फर्जी किरायेदारी के एग्रीमेंट तैयार करवाता था। पुलिस को तबस्सुम के पास से नौ डेबिट कार्ड, चार सिम, चार मोबाइल, चार पैनकार्ड, आधार, एक चेक, चेकबुक, बैंक किट और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं।

खड़े ट्रक से टकराया तेज रफ्तार वाहन, ड्राइवर केबिन में फंसा

» कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र में देर रात हादसा, पुलिस-एनएचएआई टीम ने रेस्क्यू कर निकाला

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर।महाराजपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। कानपुरङ्कप्रयागराज नेशनल हाईवे पर सरसौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने खड़े एक ट्रक में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची। राहत दल ने काफी मशक्कत के बाद चालक को केबिन से सुरक्षित बाहर निकाला। घायल की पहचान उपेंद्र यादव (32) पुत्र भुनेश्वर यादव, निवासी बेराड़ी गांव, थाना बाराचट्टी, जिला गया (बिहार) के रूप में हुई है। बताया गया कि वह फतेहपुर से कानपुर की ओर आ रहा था, तभी हादसा हो गया।घायल चालक को तत्काल सरसौल सीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे कांशीराम अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रक को हाईवे से हटवाकर यातायात सामान्य कराया है। इंस्पेक्टर राजेश कुमार के अनुसार अज्ञात वाहन की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

सम्पादकीय

फसल बीमा का लाभ मिले किसान को

एक दशक पूर्व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पीएमएफबीवाई इस मकसद से शुरू की गई थी कि देश के अन्नदाता के हित तमाम ऊंच-नीच में सुरक्षित रह सकें। सदियों से प्राकृतिक आपदाओं का त्रास पीढ़ी-दर-पीढ़ी भुगतते किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने का प्रयास मोदी सरकार ने किया था। मकसद था किसान हितों को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन जिस पीएमएफबीवाई के आज दस साल पूरे हो रहे हैं, वह आज एक चुनौतिपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। जिसके वास्तविक लाभों पर मंथन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। दरअसल, मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में खेती-किसानी में एक बड़े जोखिम को कम से कम करने का प्रयास किया था। फसल बीमा से किसानों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दरअसल, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को जलवायु और बाजारों की बढ़ती अस्थिरता से बचाना था। लेकिन विडंबना यही है कि इस योजना के अपेक्षित लाभ किसानों को नहीं मिल पाये। बल्कि यह योजना बीमा कंपनियों के लिये दुधारू गाय बनकर रह गई। यहां तक कि भाजपा शासित राज्यों हरियाणा और राजस्थान से मिली प्राथमिक जानकारी से पता चला है कि इस योजना का लाभ किसान के बजाय बीमा कंपनियां जमकर उठा रही हैं। वर्ष 2023 से 2025 के बीच, हरियाणा में बीमा कंपनियों ने पीएमएफबीवाई के तहत 2,827 करोड़ रुपये का सकल प्रीमियम एकत्र किया था। लेकिन जहां तक फसलों को हुई क्षति के लिये दावों के भुगतान का प्रश्न है, केवल 731 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया है। यानी बीमा कंपनियों को सीधे-सीधे 2,000 करोड़ से अधिक का लाभ हुआ है। इतना ही नहीं, शेष देश के आंकड़े भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। केवल तीन वर्षों में ही 82,015 करोड़ रुपये बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम के रूप में एकत्रित किए गए। जबकि किसानों को क्षतिपूर्ति के लिये मात्र 34,799 करोड़ रुपये ही वितरित किए गए। बीमा कंपनियों को 47,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ हुआ यह विडंबना ही है कि जिस महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना को किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिये लाया गया था, वो बीमा कपंनियों की मुनाफाखोरी का जरिया बन गई है। निश्चय ही देश की खाद्य सुरक्षा व किसान हित में योजना को बीमा कंपनियों के मुनाफे का जरिया बनने से रोकने की जरूरत है। बल्कि फसल बीमा योजना के क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि किसान को अधिक लाभ मिल सके। हरियाणा के कुछ हिस्सों में किसानों के दावों में की जाने वाली देरी अथवा किसानों के दावे खारिज किए जाने के खिलाफ धरना देने की बात भी सामने आई है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में फसल बीमा योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। अनुचित लाभ उठाने के लिये जाली फॉर्म और फर्जी बैंक खातों का उपयोग किया गया है। निस्संदेह, यदि बीमा कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाती रहीं और किसान को योजना का लाभ पर्याप्त रूप से न मिला, तो निश्चित रूप से किसानों का इस योजना से भरोसा उठ जाएगा। ऐसे में यदि किसान अनियमित मौसम की मार, बढ़ते कर्ज के बोझ और नौकरशाही की बाधाओं से जूझते रहे तो वे योजना का लाभ पाने से वंचित हो जाएंगे। निस्संदेह, पीएमएफबीवाई किसानों के हितों को संरक्षित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है।

लिव-इन में दहेज कानून से संरक्षण की आस

यशवंत सचदेव

लिव-इन जैसे संबंधों में भी दहेज और आर्थिक दबाव जैसे आरोप सवाल उठाते हैं। क्या संकट दहेज प्रथा में है, या हमारी सामाजिक मानसिकता में? जो आधुनिक संबंधों में भी स्वार्थ और वर्चस्व के तत्वों को पुनः स्थापित कर देती...लिव-इन जैसे संबंधों में भी दहेज और आर्थिक दबाव जैसे आरोप सवाल उठाते हैं। क्या संकट दहेज प्रथा में है, या हमारी सामाजिक मानसिकता में? जो आधुनिक संबंधों में भी स्वार्थ और वर्चस्व के तत्वों को पुनः स्थापित कर देती है? कहीं दहेज या क्रूरता के आरोप टूटते लिव-इन संबंधों को कानूनी रूप से साधने, दबाव बनाने या प्रतिशोध लेने का माध्यम तो नहीं बन रहे?हाल ही में देश को शीर्ष अदालत ने 'लोकेश बी.एच. एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य' के मामले के आपराधिक कानून से जुड़े प्रश्न पर विचार करने के लिए सहमति दी है। क्या किसी महिला के साथ विवाह जैसे संबंध (लिव-इन रिलेशनशिप) में रहने वाले पुरुष को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए के तहत क्रूरता के अपराध के लिए अभियोजन के दायरे में लाया जा सकता है या नहीं।

उल्लेखनीय है कि यह मुद्दा एक विशेष अनुमति याचिका में उठाया गया है, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के 18 नवंबर 2025 के निर्णय को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि धारा 498ए उन मामलों में भी लागू हो सकती है जहां संबंध विवाह के समान प्रकृति का हो।गौरतलब है कि धारा 498ए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि किसी महिला के साथ उसके पति अथवा पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूर व्यवहार किया जाता है, तो वह दंडनीय अपराध माना जाएगा।इसी क्रम में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस वाद में पक्षकार के रूप में सम्मिलित करते हुए उसे नोटिस जारी किया है और प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने मामले से संबंधित समस्त डिजिटल अभिलेख उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए हैं।

इसके एक पक्ष में स्त्री के अधिकार, गरिमा और सुरक्षा का संवेदनशील प्रश्न निहित है, तो दूसरे पक्ष में विधि की वह मर्यादा भी है जिसके अंतर्गत दहेज-निरोधक तथा क्रूरता संबंधी प्रावधानों को पारंपरिक रूप से वैध वैवाहिक संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। एक ओर लिव-इन संबंध भारतीय समाज में गाहे-बगाहे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं; वहीं दूसरी ओर, इनके साथ वे सभी जटिलताएं और विवाद भी सामने आ खड़े हो रहे हैं, जो प्रायः विधिसम्मत वैवाहिक संबंधों के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए जो कानून मूलतः वैवाहिक संस्था को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, उन्हीं प्रावधानों का आश्रय लेते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े कानून के दरवाजे खटखटाते हुए दिखाई दे रहे हैं।इस प्रकार, यह विमर्श केवल दंडात्मक कानून की तकनीकी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और विधिक सीमाओं के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती भी है।

सबसे अधिक विस्मयकारी पहलू यह है कि अनेक युवा तथाकथित आधुनिक जीवन-दृष्टि और स्वतंत्रता के आग्रह के साथ लिव-इन संबंधों में प्रवेश करते हैं, मानो वे सामाजिक तथा विधि-सम्मत परंपरागत व्यवस्थाओं को महत्व नहीं देते। परंतु विडंबना यह है कि जब विवाद या संकट उत्पन्न होता है, तो वही पक्ष उन कानूनी संरक्षणों की शरण में जाते दिखाई देते हैं, जो मूलतः पारंपरिक वैवाहिक संबंधों को ध्यान में रखकर निर्मित किए गए थे। यह विरोधाभास एक ओर सामाजिक मान्यताओं से विमुखता और दूसरी ओर उन्हीं से उपजे विधिक संरक्षण की अपेक्षा—कानून के समक्ष निरंतर एक नया संतुलन स्थापित करने की चुनौती उपस्थित कर रहा है।जनवरी, 2004 को 'रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम एवं अन्य के मामले' में देश की शीर्ष अदालत ने कहा 'धारा 498ए को लागू करने के लिए 'पति' शब्द के अंतर्गत कौन-कौन आएगा, यह प्रश्न वास्तव में जटिल है।

माता-पिता की देखभाल के लिए जवाबदेही सुनिश्चित हो

प्रवासी संतानों की बेरुखी

पुष्परंजन

विदेशों में बसी संतानों द्वारा भारत में रह रहे मां-बाप की उपेक्षा व अनदेखी का मामला संसद में उठना केवल कानूनी सवाल ही नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक मुद्दा भी है। कानून द्वारा प्रवासी बच्चों के माता-पिता का जीवन सुरक्षित करना वक्त की जरूरत है।भारतीय समाज में परिवार की संरचना और मूल्यों का आधार माता-पिता की सेवा और सम्मान रहा है, लेकिन आधुनिक समय में बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों के कारण लाखों युवा विदेशों में बस रहे हैं। यह प्रवास अक्सर परिवारों के लिए आर्थिक उन्नति लाता तो है, लेकिन कई मामलों में बुजुर्ग माता-पिता भारत में अकेले पड़ जाते हैं। उनकी देखभाल, भावनात्मक समर्थन और नियमित संपर्क की कमी से बुजुर्गों की मानसिक और शारीरिक स्थिति दयनीय हो जाती है।

हाल ही में राज्यसभा में भाजपा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने विदेश जाने वाले युवाओं द्वारा माता-पिता की देखभाल सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि विदेश जाने से पहले बच्चों से एक हलफनामा लिया जाए, जिसमें वे अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा माता-पिता की देखभाल के लिए देने का वादा करें। इसके साथ ही, हर छह महीने में माता-पिता से 'संतुष्टि प्रमाण पत्र' प्राप्त करना अनिवार्य हो। ऐसा प्रमाण पत्र न मिलने या शिकायत आने पर बच्चों का पासपोर्ट रद्द किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कम से कम सप्ताह में एक बार फोन पर माता-पिता का हालचाल पूछना भी बाध्यकारी होना चाहिए। इस संदर्भ में पिछले वर्ष 500 से अधिक ऐसे मामले सामने आए, जहां विदेश में बसे बच्चों की उपेक्षा के कारण माता-पिता की हालत बहुत खराब हो गई या उनकी मृत्यु हो गई। विडंबना है कि बच्चे अंतिम

संस्कार के लिए भी नहीं लौटे।यह मुद्दा केवल भावनात्मक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और कानूनी दृष्टि से भी गंभीर है। भारत में पहले से ही 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007' लागू है, जो बच्चों को माता-पिता की आर्थिक और भावनात्मक देखभाल के लिए जिम्मेदार बनाता है। इस कानून के तहत बुजुर्ग ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं और बच्चों से मासिक भरण-पोषण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें संपत्ति हस्तांतरण रद्द करने की शक्ति भी शामिल है।हालांकि, यह कानून विदेश में बसे बच्चों (एनआरआई) पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार, प्रवर्तन की कमी और संपर्क की दूरी जैसी समस्याएं आड़े आती हैं। कई एनआरआई बच्चे भारत में संपत्ति या बैंक खाते रखते हैं, लेकिन देखभाल की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। सांसद का प्रस्ताव इसी कमी को दूर करने का प्रयास है। यदि पासपोर्ट आवेदन या वीजा प्रक्रिया में माता-पिता की सहमति अनिवार्य हो सकती है, तो यह उनके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा।इस तरह के कानून की आवश्यकता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि भारत में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। प्रवास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा और भावनात्मक समर्थन की कमी होती है। कई मामलों में माता-पिता ने बच्चों को विदेश भेजने के लिए अपनी ज़मीन-जायदाद बेच दी, कर्ज लिया या अपनी सारी बचत लगा दी, लेकिन बदले में उन्हें अकेलापन और उपेक्षा मिली।

भारतीय संस्कृति में 'मातृ-पितृ भक्ति' को सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन आर्थिक महत्वाकांक्षा और पश्चिमी जीवनशैली के प्रभाव से यह मूल्य कमजोर पड़ रहे हैं। यह मुद्दा सांस्कृतिक संकट पर भी ध्यान आकर्षित करता है। निःसंदेह, सफलता के पीछे माता-पिता का बहुत बड़ा त्याग होता है।हालांकि, इस प्रस्ताव पर बहस भी छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे सकारात्मक मानते हैं, क्योंकि यह बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करेगा और बच्चों में जिम्मेदारी की भावना जाग्रत करेगा। दूसरी ओर, आलोचक इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण बताते हैं। वे कहते हैं कि पासपोर्ट रद्द करना या प्रमाण पत्र की बाध्यता जैसे कदम बहुत कठोर हैं, जो प्रवास की स्वतंत्रता को प्रभावित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पासपोर्ट रद्द करने के लिए केवल गंभीर अपराध या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार होते हैं।

उत्तरीपुरा में डीएम का धान क्रय केंद्रों पर छापा

स्वास्थ्य केंद्र में भी मिली लापरवाही

पीएचसी में चार कर्मी गैरहाजिर, वेतन काटने के आदेश, वेटलैंड क्षेत्र से कब्जा हटाने के भी निर्देश

स्वराज इंडिया न्यूज

बिल्हौर/कानपुर। कानपुर जिले में प्रशासनिक सख्ती का बड़ा संदेश देते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने उत्तरीपुरा क्षेत्र में धान क्रय केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर औचक छापा मारकर व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। किसानों की लगातार शिकायतों पर डीएम ने नवीन मंडी स्थल उत्तरीपुरा पहुंचकर खरीद व्यवस्था की हकीकत परखी, जहां टोकन होने के बावजूद धान न तौलने और कई दिनों से किसानों को चक्कर कटवाने की पुष्टि हुई। मौके पर जिम्मेदार अधिकारियों के जवाब संतोषजनक न मिलने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मंडी परिसर में अव्यवस्था, गंदगी और खरीदे गए धान का खुले में पड़ा होना भी मिला। डीएम ने साफ कहा कि पात्र किसानों का धान हर हाल में खरीदा जाए, छोटे किसानों को प्राथमिकता

➪ किसानों की शिकायत पर सख्त हुए डीएम, निलंबन की संस्तुति व जांच समिति गठित

जैसरमऊ वेटलैंड को मॉडल बनाने की तैयारी

बिल्हौर की गंगा कटरी स्थित जैसरमऊ वेटलैंड का भी संयुक्त निरीक्षण कर डीएम ने इसे "वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड" योजना के तहत विकसित करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। करीब छह हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस वेटलैंड की ड्रोन मैपिंग से सीमांकन कर अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। यहां बर्ड टॉवर, वॉच टॉवर और बर्ड वॉचिंग पाथ-वे विकसित करने की योजना है। प्रशासन का कहना है कि वैज्ञानिक संरक्षण और कड़ी निगरानी से इसे जिले की नई पर्यावरणीय पहचान बनाया जाएगा।

मिले और दोबारा शिकायत मिलने पर सीधे दंडात्मक कार्रवाई होगी।

धान खरीद में गड़बड़ी पर सख्त रुख

नवीन मंडी स्थल उत्तरीपुरा में खाद्य विभाग के तीन और यूपीएसएस का एक धान क्रय केंद्र संचालित मिला। किसानों ने डीएम को बताया कि टोकन जारी होने के बाद भी तौल नहीं हो रही। कुछ किसान दिसंबर से खरीद का इंतजार कर रहे हैं। अभिलेख जांच में सामने आया कि यूपीएसएस केंद्र पर 12 फरवरी के बाद कोई खरीद दर्ज नहीं हुई, जबकि किसान लगातार आ रहे थे। साथ ही 14 नवंबर के बाद किसी वरिष्ठ अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण भी नहीं हुआ। इसे गंभीर शिथिलता मानते हुए डीएम ने विपणन निरीक्षक के निलंबन की संस्तुति शासन को भेजने के निर्देश दिए और जिला खाद्य विपणन अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने को कहा। धान खरीद की पूरी प्रक्रिया की जांच के लिए एसडीएम बिल्हौर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए।

पीएचसी उत्तरीपुरा में भी खुली लापरवाही

धान क्रय केंद्रों के बाद डीएम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उत्तरीपुरा का औचक निरीक्षण किया, जहां सात में से चार कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। अनुपस्थित कर्मियों में मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय शामिल रहे। डीएम ने अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। चीफ फार्मासिस्ट का अवकाश भी विधिवत स्वीकृत न मिलने पर वेतन कटौती के निर्देश हुए। ओपीडी रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में नहीं मिला और मरीजों के मोबाइल नंबर भी दर्ज नहीं थे। बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली बंद और सफाई व्यवस्था खराब पाई गई। संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब कर सभी स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए।

एक नजर में...

- डीएम ने उत्तरीपुरा धान क्रय केंद्रों पर औचक निरीक्षण किया
- टोकन के बावजूद किसानों का धान न तौलने की शिकायत सही पाई गई
- विपणन निरीक्षक के निलंबन की संस्तुति के निर्देश
- जिला खाद्य विपणन अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का आदेश
- धान खरीद की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित होगी
- मंडी में गंदगी और धान का खुले में भंडारण मिला
- पीएचसी निरीक्षण में 7 में से 4 कर्मचारी गैरहाजिर
- अनुपस्थित कर्मियों के वेतन काटने और स्पष्टीकरण तलब
- जैसरमऊ वेटलैंड के सीमांकन व कब्जा हटाने के निर्देश
- वेटलैंड को मॉडल इको-ज़ोन के रूप में विकसित करने की तैयारी

द लायर्स एसोसिएशन में कुशल पांडेय की महामंत्री पद पर शानदार जीत

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। तहसील में द लायर्स एसोसिएशन के चुनाव ने मंगलवार को पूरे परिसर का माहौल गर्माए रखा। अधिवक्ताओं ने उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया और अंततः महामंत्री पद की जिम्मेदारी कुशल पांडेय को सौंप दी। मतदान सुबह शुरू होते ही वकीलों की आवाजाही तेज हो गई। सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग कराई गई। 141 में से 136 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

निर्धारित समय तक मतदान पूरा होने के बाद मतगणना शुरू हुई, जिसका परिणाम दोपहर बाद घोषित किया गया। महामंत्री पद के लिए कुशल पांडेय और विशाल सैनी आमने-सामने थे। गिनती पूरी होने पर कुशल पांडेय को 71 मत मिले, जबकि विशाल सैनी को 60 मत प्राप्त हुए। नतीजे आते ही समर्थकों ने एक-दूसरे को बधाई दी और परिसर में खुशी का माहौल बन गया। द लायर्स एसोसिएशन के चुनाव की खास बात यह रही

➪ कड़े मुकाबले में 11 मतों से जीत, समर्थको ने फूल मालाओं से लादा

जीत के बाद निकला विजय जुलूस

परिणाम घोषित होते ही युवा अधिवक्ता कुशल पांडेय के समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने उन्हें फूलमालाओं से लाद दिया और नारेबाजी के बीच जुलूस निकाला। विजयी जुलूस तहसील परिसर से निकलकर नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ कोतालेश्वर मंदिर और वखण्डेश्वर मंदिर पहुंचा, जहां नवनिर्वाचित महामंत्री ने समर्थकों के साथ माथा टेककर आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूरे रास्ते समर्थकों में जीत का जश्न देखने को मिला।

कि कई पदों पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका था। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष समेत कुल 18 पदों पर एक-एक नामांकन होने के कारण प्रत्याशियों को निर्विरोध घोषित किया गया।

तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। कानपुर-अलीगढ़ हाईवे पर मंगलवार देर रात मेडुआ गांव के पास सीएनजी पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी। हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की उपचार के दौरान मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक कन्नौज जनपद के तिर्वा क्षेत्र के ठठिया गांव निवासी 24 वर्षीय सौरभ राठौर अपने साथी आकाश के साथ बाइक से कन्नौज की ओर जा रहे थे। रात करीब 11 बजे उनकी बाइक अचानक संतुलन खो बैठी और डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे।प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हौर ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने सौरभ को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल आकाश को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर कर दिया गया। इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला तेज रफ्तार के कारण बाइक के अनियंत्रित होने का प्रतीत हो रहा है। परिजनों को सूचना दे दी गई है।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की आरोपितों की तलाश

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, प्यार का झांसा, फिर गैंगरेप

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर। बिल्हौर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया के जरिए पनपी दोस्ती एक विवाहित महिला के लिए भयावह साबित हुई। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई बातचीत ने पहले भरोसा और नजदीकियाँ हासिल की और फिर इसी विश्वास का फायदा उठाकर युवक और उसके साथियों ने कथित तौर पर महिला का शारीरिक शोषण किया।

पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी पहचान इंस्टाग्राम पर शिवराजपुर निवासी शरद यादव से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आरोपी ने महिला का विश्वास जीत लिया। आरोप है कि इसी दौरान उसने महिला का आपत्तिजनक

वीडियो बना लिया।इसके बाद आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि दबाव बनाकर आरोपी ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, बाद में उसने अपने कुछ साथियों को भी इस कृत्य में शामिल कर लिया, जिसके बाद महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर आरोपी लगातार धमकियां देता रहा और कथित तौर पर वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया।घटना की जानकारी जब महिला के पति को हुई तो उन्होंने आरोपी से फोन पर बात की। आरोप है कि आरोपी ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म, आईटी एक्ट और एससी/एसटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हैं।

केडीए में 5 बजे के बाद इंट्री पर की गई सख्ती

दलालों और बाहरी लोगों के अनियंत्रित प्रवेश पर उपाध्यक्ष की निगरानी

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण में दलालों और बाहरी लोगों के अनियंत्रित प्रवेश पर अब सख्ती शुरू कर दी गई है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्दयाल के निर्देश पर कार्यालय परिसर में प्रवेश व्यवस्था को कड़ा करते हुए नया समय-नियंत्रण लागू कर दिया गया है।निर्देशों के अनुसार अब शाम 5:00 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को प्राधिकरण परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केवल अत्यंत आवश्यक कार्य होने की स्थिति में ही संबंधित अधिकारी की अनुमति लेकर प्रवेश मिल सकेगा। इसके लिए उच्च स्तर से स्पष्ट सहमति अनिवार्य कर दी गई है।बताया गया है कि लंबे समय से प्राधिकरण कार्यालय में दलालों और बाहरी लोगों की आवाजाही को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। कई मामलों में यह भी सामने आया था कि कार्यालय समय समाप्त होने के बाद भी अनधिकृत लोग परिसर में मौजूद रहते थे, जिससे कार्य-प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था

प्रभावित होती थी।इसी को देखते हुए उपाध्यक्ष ने सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। आदेश लागू होते ही सुरक्षा अधिकारी और गार्ड शाम के समय सक्रिय नजर आए। उन्होंने निर्धारित समय के बाद आने वाले लोगों को प्रवेश द्वार पर ही रोककर नियमों की जानकारी दी और बिना अनुमति अंदर जाने से मना कर दिया गया. वीसी ने कहा कि इस व्यवस्था से दलाली प्रथा पर रोक लगेगी, कार्यालय की सुरक्षा मजबूत होगी और आम नागरिकों के कार्य पारदर्शी ढंग से निपटाए जा सकेंगे। आने वाले दिनों में प्रवेश व्यवस्था को और व्यवस्थित बनाने के लिए पहचान-पंजीकरण प्रणाली लागू करने की भी तैयारी चल रही है।

लोगों का प्रवेश रोकते सुरक्षा कर्मी

लापता बालक का रजबहे में उतराता हुआ मिला शव

» माँ के साथ बुआ के घर गया था बालक, महिला के पति की पहले ही हो चुकी मौत

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। शिवली के ग्राम राजपुर गांव में एक मासूम खेलते समय कहीं अचानक लापता हो गया। काफी तलाश के बाद कहीं कुछ पता नहीं चला। बुधवार की सुबह शिवली रजबहे में बरार गांव के पास उसका शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव की पहचान करने के साथ आवश्यक कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।शिवली के चंपतपुर बारा खेड़ा निवासिनी कुमकुम कुमारी ननद सुनीता सिंह निवासी राजपुर के घर गई थी। वह अपने दो वर्षीय बेटे कार्तिक को भी साथ ले गई थी। कार्तिक मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे खेलते समय अचानक कहीं गायब हो गया। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। बुधवार की सुबह करीब 1 किलोमीटर दूर बरार गांव के पास से निकले शिवली रजबहे में उसका शव पड़ा मिला। शव देख ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। जानकारी पर परिजनों ने वहां पहुंचकर मृतक कार्तिक की पहचान की और चीख पुकार मच गई। मां कुमकुम कुमारी, बाबा शिवराम कमल का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले पंचायत लनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

मिलावटी मावा पर सख्ती

व्यापारियों को चेतावनी, संदिग्ध निर्माताओं से खरीद पर रोक

त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हटिया खोआ मंडी में जनजागरूकता बैठक

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर। आगामी त्योहारों के मद्देनज़र आम जनता को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय संजय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हटिया खोआ मंडी में व्यापारियों और आढ़तियों के साथ जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जनपद में मिलावटी खोआ के विक्रय, वितरण, भंडारण और निर्माण पर पूर्ण रोक सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। व्यापारियों को निर्देशित किया गया कि वे किसी भी संदिग्ध या मिलावटी खोआ निर्माता से खोआ की खरीद न करें। साथ ही मिलावट की कड़ी को तोड़ने के लिए ऐसे निर्माताओं की जानकारी तत्काल विभाग को उपलब्ध कराने को भी कहा गया।

कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने भी मिलावट रोकने के लिए सहयोग का भरोसा दिया। खोआ व्यापार

मंडल ने सर्वसम्मति से विजातीय वसा की जांच के लिए बीआर रीडिंग मशीन खरीदने का निर्णय लिया है, जिससे बाहरी वसा की मिलावट का तुरंत पता लगाया जा सकेगा। यह कदम मंडी स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

खोआ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही व्यापार मंडल कार्यालय में ब्यूटायरो-रिफ्रैक्टोमीटर स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से मंडी में आने वाले खोआ की गुणवत्ता की जांच संभव होगी और विजातीय वसा युक्त खोआ की आपूर्ति पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। बैठक में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा खोआ व्यापार मंडल के विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। विभाग ने संकेत दिया है कि त्योहारों के दौरान जांच और प्रवर्तन कार्रवाई और अधिक सख्ती से जारी रहेगी।

पीएमश्री प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की प्रस्तुतियों ने मोहा मन

संगसियापुर पीएम श्री विद्यालय में आयोजित किया गया भव्य वार्षिकोत्सव

» स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर देहात। विकासखंड क्षेत्र के पीएमश्री प्राथमिक विद्यालय संगसियापुर में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम भारत की विविधता, देश की एकता रही। समारोह का शुभारंभ मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ।

कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी मनोज पटेल, पूर्व एबीआरसी अरविंद सिंह सेंगर, पूर्व एआरपी नवजोत यादव, एसएमसी अध्यक्ष विपिन, प्रधान पद प्रत्याशी देवेंद्र सेंगर, राम प्रकाश और शिवम सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों का पारंपरिक तिलक व बैज लगाकर स्वागत किया गया।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में छात्रों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, जय होफ़, विविधता में एकता पर आधारित लोकगीत, हरियाणवी लोकनृत्य और मेड इन इंडिया गीत प्रस्तुत किया। बच्चों द्वारा योग प्रदर्शन और रंग दे बसंती चोलाफ़ पर प्रस्तुति को भी खूब सराहना मिली। सबसे आकर्षक प्रस्तुति आदिवासी नृत्य रही, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। खेलकूद प्रतियोगिताओं में विजेता और बहुमुखी प्रतिभा वाले छात्र-छात्राओं को ट्रॉफी व मेडल देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में विप्रो फाउंडेशन की परियोजना के अंतर्गत बच्चों को जल संरक्षण विषय पर कार्य करने हेतु प्रमाणपत्र और बैग प्रदान किए गए। कंचन कामिनी द्वारा पिछले 3 वर्षों से बच्चों में जल जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर उनकी संपादित पुस्तक फ़शिक्षक राष्ट्र निर्माताफ़ खंड शिक्षा अधिकारी को भेंट की गई।

खंड शिक्षा अधिकारी ने छात्रों और शिक्षकों को सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा ही जीवन में सफलता का सबसे सशक्त साधन है।

कार्यक्रम का समापन प्रधानाध्यापक रणजीत सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

मामा के रुपये वापस न कर पाने पर महिला ने फांसी लगाकर दी जान

पति को बिना जानकारी दिए महिला ने रख दिये थे गिरवी जेवर

वंदना देवी (फाइल फोटो)

» स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर देहात। रसूलाबाद के मकरंदपुर कहिंजरी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में मातम छा गया। मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल शुरू की।रसूलाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मकरंदपुर कहिंजरी गांव में वंदना देवी (24) ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर की दूसरी मंजिल के बरामदे में दुपट्टे से पंखे के सहारे फांसी लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक महिला का मायका बिल्हा उसरी में था। उसका विवाह मकरंदपुर कहिंजरी में संदीप कुमार से हुई थी। संदीप कहिंजरी के निजी स्कूल में अपनी इको वैन लगाए हुए था। जिसके चलते संदीप ने करीब एक माह अपनी पत्नी को भी शिक्षिका के रूप में विद्यालय में तैनात करवा दिया था। मंगलवार की दोपहर को वंदना विद्यालय की निर्धारित छुट्टी से पहले सिर दर्द छुट्टी लेकर घर पहुंची और घर की दूसरी मंजिल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति ने बताया कि उसकी पत्नी ने अपने जेवर को गिरवी रखने के बाद मामा सुनील को कर्ज का पैसा न चुका पाई थी। जिससे वह मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहती थी लेकिन उसको इस बात की जानकारी नहीं थी। जिसके चलते उसकी पत्नी ने यह कदम उठाया।

रमज़ान का चांद आज नज़र आने की उम्मीद, तरावीह से होगी इबादतों की शुरुआत

सहरी के साथ रखे जाएंगे रोज़े, बाज़ारों में बढ़ी रौनक और रूहानी माहौल

जानकारी देते मौलाना नायाब खान अजहरी

रमजान में रसूलाबाद में सजी फल की दुकानें

» स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर देहात। मुकद्दस और बरकतों से भरे रमज़ान महीने का चाँद आज दिखाई देने की उम्मीद है। चाँद नज़र आते ही मुस्लिम समुदाय में खुशी और अकीदत का माहौल बन जाएगा। लोग एक-दूसरे को चाँद की मुबारकबाद देते हुए रमज़ान के पवित्र महीने का इस्तकबाल करेंगे। चाँद दिखने के बाद रात में मस्जिदों में तरावीह की नमाज़ अदा की जाएगी और सहरी के साथ रोज़ों का सिलसिला शुरू हो जाएगा।रमज़ान को इस्लाम में बेहद अफज़ल और रहमतों वाला महीना माना गया है। इस पूरे माह में रोज़ा, नमाज़, क़ुरआन पाक की तिलावत, जकात और फितरा के जरिए बंदा अपने रब की इबादत करता है और अपने दिल व अमल को पाक करने की कोशिश करता है। इसे सब्र, इख़लाक़, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देने वाला महीना भी कहा जाता है।स्थानीय आलिम मौलाना नायाब खान अजहरी ने बताया कि रमज़ान का पाक महीना रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का पैगाम लेकर आता है। रोज़ा इंसान को परहेज़गार बनाता है और गुनाहों से बचने की तालीम देता है। उन्होंने कहा कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान में जकात और फितरा जरूरतमंदों तक जरूर पहुँचाएं, ताकि गरीब और मिस्कीन भी ईद की खुशियों में बराबर के शरीक हो सकें।रमज़ान की आमद को लेकर कस्बे और आसपास के इलाकों के बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। फलों, खजूर, सूखे मेवे और सहरी-इफ्तार से जुड़ी चीज़ों की दुकानों पर भीड़ दिखाई दे रही है। शाम ढलते ही इबादत और तैयारी का माहौल और गहरा हो गया है।

एक नजर में..

- आज शाम रमज़ान का चाँद नज़र आने की उम्मीद
- चाँद दिखते ही रमज़ान माह का होगा आगाज़
- रात में मस्जिदों में अदा होगी तरावीह की नमाज़
- सहरी के साथ शुरू होंगे रोज़े
- जकात और फितरा देने पर दिया गया ज़ोर
- फलों और इफ्तार सामग्री की दुकानों पर बढ़ी

मत्स्य विभाग में बड़ा एक्शन

कानपुर मंडल के उपनिदेशक समेत पूरा स्टाफ मुख्यालय अटैच

» भ्रष्टाचार पर मंत्री का कड़ा प्रहार, लगातार शिकायतों और प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं उजागर

» मंत्री के निर्देश पर महानिदेशक की कार्रवाई, निरीक्षक निलंबित, नए अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। मत्स्य पालन और उत्पादन से जुड़ी केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों पर सख्त रुख अपनाते हुए मत्स्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक एक्शन किया गया है। विभागीय मंत्री डॉ. संजय निषाद के निर्देश पर कानपुर मंडल और जनपद स्तर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाकर मुख्यालय लखनऊ से अटैच कर दिया गया है।

इन अधिकारियों-कर्मचारियों को किया गया संबद्ध

- उपनिदेशक मत्स्य - सुनीता वर्मा
- मत्स्य विकास अधिकारी - कुसुम पाल
- अपर सांख्यिकीय अधिकारी - केसी वर्मा
- उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ सहायक – आयशा खातून
- कनिष्ठ सहायक - अमरीश अवस्थी
- वरिष्ठ सहायक - प्रतिमा उमराव
- कनिष्ठ सहायक - प्रबल कुमार
- सोहन लाल, सतीष (मछुआ), अजय

कार्रवाई के दायरे में मंडलीय उपनिदेशक से लेकर जिला कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी तक शामिल हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी, शिकायतों की अनदेखी और संदिग्ध कार्यशैली को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया।बताया गया है कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि कई अधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे थे और कुछ मामलों में भ्रष्टाचार से जुड़ी संलिप्तता भी पाई गई। मंडलीय स्तर के अधिकारियों पर अधीनस्थ कर्मचारियों को संरक्षण देने के आरोप भी दर्ज हुए हैं। मंत्री के निर्देश पर

महानिदेशक मत्स्य धनलक्ष्मी ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करते हुए कानपुर मंडल के सभी 10 अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया।

निलंबन और नई तैनाती भी

कार्रवाई के तहत सहायक निदेशक कार्यालय में तैनात वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक सुनील कुमार को निलंबित कर दिया गया है। वहीं बुलंदशहर के सहायक मत्स्य अधिकारी जितेंद्र कुमार को कानपुर मंडल से संबद्ध किया गया है। उपनिदेशक मत्स्य सृष्टि यादव को कानपुर मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ताकि विभागीय कार्य प्रभावित न हो।विभागीय मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि योजनाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

चलती ट्रेन में टीटीई ने केबिन में ले जाकर किया दुष्कर्म, फरार होने पर 10 हजार रुपए का इनाम

एसी फर्स्ट कोच बना वारदात का ठिकाना, निलंबन के बाद गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

गोरखपुर। चलती ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाली एक गंभीर आपराधिक घटना सामने आई है। गोरखपुरङ्कअहमदाबाद एक्सप्रेस में तैनात एक टीटीई पर 22 वर्षीय युवती से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत के बाद रेलवे प्रशासन ने आरोपी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि जीआरपी ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी हैं। आरोपी घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पीड़िता मऊ जिले की निवासी है और गोरखपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। वह परीक्षा देकर लौट रही थी। ट्रेन छूटने की जल्दबाजी में टिकट नहीं ले सकी और जनरल कोच में चढ़ गई। आरोप है कि टिकट जांच के दौरान टीटीई ने उसे बिना टिकट यात्रा में पकड़ लिया और भारी जुर्माना व कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया।

पीड़िता के बयान के मुताबिक, टीटीई ने कहा कि वह चाहें तो ÷मामला निपटा÷ सकता है और उसे सीट भी दिला देगा। इसी बहाने वह युवती को एसी प्रथम श्रेणी कोच के एक खाली केबिन में ले गया। अंदर पहुंचते ही दरवाजा बंद कर जबरन दुष्कर्म किया। युवती के विरोध और शोर मचाने पर आरोपी ने उसे धमकाया कि शिकायत करने पर चोरी और बिना टिकट यात्रा समेत कई धाराओं में फंसा देगा।

बताया जाता है कि वारदात के बाद युवती सदमे में केबिन से बाहर निकली और दूसरे यात्रियों से मदद मांगी। इसके बाद उसने मोबाइल से आपात सेवा नंबर पर कॉल कर पूरी घटना की सूचना दी। कंट्रोल रूम से मैसेज फ्लैश होते ही अगले स्टेशनों पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट कर दी गईं।

सूत्रों के अनुसार, देवरिया के आसपास ट्रेन की रफ्तार धीमी होने पर आरोपी टीटीई कोच से उतरकर भाग निकला। इसके बाद से उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों, रिश्तेदारों और परिचितों के यहां दबिश शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां ट्रेन के संबंधित कोच, केबिन और कॉरिडोर के सीसीटीवी फुटेज (जहां उपलब्ध) खंगाल रही हैं। सहयात्रियों और ट्रेन स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा सकें। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर रिपोर्ट केस डायरी में शामिल की जा रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर आपराधिक कदाचार का है। विभागीय जांच भी अलग से शुरू कर दी गई है। दोष सिद्ध होने पर आरोपी कर्मचारी की सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई संभव है।

फर्जी दरोगा बनकर फैलाया नौकरी का जाल

वर्दी असली, पिस्तौल लाइटर निकली, इनकम टैक्स अफसर की गाड़ी से चलता था ठगी रैकेट

» होटल में इंटरव्यू, स्कूल में नकली परीक्षा, सचिवालय और हाईकोर्ट में भर्ती का झांसा देकर बेरोजगारों से ठगी, पुलिस ने वर्दीधारी ठग को दबोचा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। वर्दी असली, रौब असली जैसा, लेकिन कहानी पूरी तरह फर्जी। अनवरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो खुद को दरोगा बताकर बेरोजगार युवाओं से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का रैकेट चला रहा था। आरोपी इनकम टैक्स कमिश्नर की फर्जी प्लेट लगी कार में घूमता था और लोगों पर धौंस जमाता था।मुखबिर की सूचना पर कालपी रोड के पास पुलिस ने संजय कुमार सिंह (42) को दबोचा। वह उन्नाव का निवासी है और लंबे समय से फर्जी पहचान के सहारे लोगों को जाल में फंसा रहा था। गिरफ्तारी के समय वह पूरी पुलिस वर्दी में था, कंधे पर स्टार लगे थे और कमर में पिस्टल टंगी थी। जांच में खुलासा हुआ कि उसकी कमर में लगी पिस्टल असली नहीं, बल्कि सिगरेट जलाने वाला लाइटर थी। साथ ही उसके पास से 8 नकली कारतूस भी बरामद किए गए, जो सिर्फ दिखावे के लिए रखे गए थे।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह अपने साथियों दुर्गेश कुमार सविता और विजय सिंह चौहान के साथ मिलकर सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देता था। गिरोह बेरोजगार युवाओं को सचिवालय और हाईकोर्ट में भर्ती का भरोसा दिलाता था। इसके लिए लखनऊ में होटल और निजी स्कूल किराये पर लेकर फर्जी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू तक कराए जाते थे। चयन परिणाम के नाम पर युवाओं को महीनों तक टहलाया जाता और वर्दी का रौब दिखाकर सवाल पूछने से रोका जाता था।

तलाशी के दौरान आरोपी की कार से फर्जीवाड़े का बड़ा जखीरा मिला। बरामद सामान में पुलिस की फर्जी आईडी, सीबीआई के दो नकली कार्ड, मुंबई पुलिस का कार्ड, कई बैंकों की चेकबुक, मोहरें और नकदी शामिल है। कार पर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की फर्जी नंबर प्लेट लगी थी, जबकि असली नंबर प्लेट सीट के नीचे छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। साथियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि गिरोह से जुड़े और मामलों का भी खुलासा होने की संभावना है।

यूपी बोर्ड परीक्षाओं का आगाज, कड़ी सुरक्षा के बीच लाखों परीक्षार्थी शामिल

» प्रश्नपत्र सुरक्षा पर सख्ती, स्ट्रांग रूम की रात में होगी आकस्मिक जांच, जिओलोकेशन फोटो अनिवार्य

करीब 55 लाख परीक्षार्थी दे रहे हैं परीक्षा, प्रदेश में बनाएं गए 8 हजार से अधिक परीक्षा केंद्र

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं आज से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई हैं। इस वर्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में लगभग 55 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भर में करीब 8 हजार से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां बहुस्तरीय निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। शासन ने प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।

शासन के आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर बनाए गए स्ट्रांग रूम की रात्रिकालीन आकस्मिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा) के निर्देश पर संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षकों को स्वयं निरीक्षण करने तथा अलग-अलग टीमें गठित कर सतत निगरानी रखने को कहा गया है। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी नामित अधिकारी रात के समय परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर स्ट्रांग रूम का भौतिक सत्यापन करेंगे। निरीक्षण के दौरान स्ट्रांग रूम के सामने जिओलोकेशन युक्त फोटोग्राफ लेना और उसे निर्धारित समूह में तत्काल साझा करना अनिवार्य होगा, ताकि निगरानी की रियल-टाइम पुष्टि हो सके।इसके अलावा प्रत्येक निरीक्षण दल को प्रतिदिन की जांच रिपोर्ट ऑनलाइन प्रपत्र के माध्यम से अपलोड करनी होगी। इससे प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, सील की स्थिति और केंद्र की व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। शासन ने स्पष्ट किया है कि इस बार नकल रोकने के लिए उड़नदस्ता दल, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत की गई है। किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी और केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

यह भी जान लीजिए

» स्ट्रांग रूम की रात में आकस्मिक जांच अनिवार्य

» निरीक्षण के समय जिओलोकेशन फोटो जरूरी

» दैनिक रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड होगी

» नकल रोकने को उड़नदस्ता और मजिस्ट्रेट तैनात

» पहले दिन ही इटावा में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया

इटावा में पहले दिन ही मुन्ना भाई पकड़ा गया

इटावा। बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन प्रथम पाली में बकेवर क्षेत्र के एक परीक्षा केंद्र पर दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दे रहे युवक को पकड़ लिया गया। सूत्रों के अनुसार निवाड़ी कला निवासी एक युवक किसी अन्य छात्र के स्थान पर परीक्षा देने सेंटर में प्रवेश कर चुका था और पेपर भी लिख रहा था। जांच के दौरान पहुंची अधिकारियों की टीम को संदेह होने पर सत्यापन किया गया, जिसमें फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया। उपजिलाधिकारी भरथना मौके पर पहुंचीं और युवक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

स्कूल बना 'चाय सेवा केंद्र', पढ़ाई करती रही इंतज़ार

» देर से खुला विद्यालय, बच्चों से मंगवाई गई चाय पत्ती, शिक्षा सुधार के दावों पर उठे सवाल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद। प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने और स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के सरकारी दावों की हकीकत जमीनी स्तर पर कितनी खोखली है, इसकी एक तस्वीर ब्लॉक मोहम्मदाबाद क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में देखने को मिली। यहां पढ़ाई से ज्यादा तवज्जो चाय व्यवस्था को दी गई और अनुशासन की जगह लापरवाही का बोलबाला दिखा।

प्राथमिक विद्यालय ऊगरपुर टिमरुआ पिपरगांव में बुधवार को स्कूल समय से देर से खुला। निर्धारित समय सुबह 9 बजे का है, लेकिन विद्यालय परिसर में न तो समय पर शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हुईं और न ही व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखीं। हालात यह रहे कि पढ़ाई शुरू कराने के बजाय शिक्षक द्वारा बच्चों को गांव की दुकान से चाय पत्ती लाने के लिए भेज दिया गया।

बच्चे बस्ता छोड़कर 'दौड़-भाग ड्यूटी' निभाते नजर आए।विद्यालय में 11 बजे तक न तो कक्षाएं संचालित हो रही थीं

और न ही परिसर की साफ-सफाई पूरी हुई थी। इस बीच चाय बनकर तैयार हो गई और स्टाफ चाय की चुस्कियों में व्यस्त दिखा, जबकि बच्चे इधर-उधर खेलते रहे। शिक्षा का समय यूं ही फिसलता रहा। मिड डे मील रसोई में भोजन बनता जरूर मिला, लेकिन वहां भी व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं दिखीं। बच्चों को दूध वितरण किया जा रहा था,

मगर पढ़ाई का माहौल पूरी तरह गायब था।मौके पर जब वीडियो बनाया जाने लगा तो प्रधानाध्यापिका ने आपत्ति जताते हुए मोबाइल छीनने की कोशिश की और कहा कि पहले अधिकारियों से बात की जाए। बाद में फोन पर एक व्यक्ति ने खुद को अधिकारी बताकर बात की, लेकिन जानकारी करने पर पता चला कि वह शिक्षिका के पति थे, जो अधिकारी बनकर बात कर रहे थे। इससे पूरे घटनाक्रम पर और सवाल खड़े हो गए। सरकार द्वारा छात्र संख्या बढ़ाने, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और पारदर्शिता लाने के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ स्कूलों की कार्यप्रणाली इन प्रयासों पर पानी फेरती नजर आ रही है।

खबर: एक नजर में...

» निर्धारित समय के बाद खुला विद्यालय

» पढ़ाई के बजाय बच्चों को चाय पत्ती लाने भेजा गया

» 11 बजे तक कक्षाएं शुरू नहीं हुईं

» परिसर में साफ-सफाई अधूरी मिली

» मिड डे मील में भी अव्यवस्था के संकेत

» वीडियो बनाने पर प्रधानाध्यापिका ने किया विरोध

» फोन पर 'अधिकारी' बनकर बात करने वाला निकला परिजन

» शिक्षा सुधार के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर

रामनगरी में मरीजो का इलाज 'राम भरोसे'

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। राम मंदिर निर्माण के बाद देश-विदेश से श्रद्धालुओं की आमद बढ़ी है, लेकिन रामनगरी की सबसे बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था जिला अस्पताल आज खुद इलाज के लिए जूझ रहा है। 212 बेड वाले जिला अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी ने व्यवस्था को लगभग फराम भरोसेफ छोड़ दिया है।

» 50 पदों पर सिर्फ 20 डॉक्टर, जिला अस्पताल बदहाल

» विशेषज्ञों के बिना चल रहा 212 बेड का अस्पताल

अस्पताल में चिकित्सकों के 50 स्वीकृत पद हैं, लेकिन वर्तमान में महज 20 डॉक्टर ही सेवाएं दे रहे हैं। हाल यह है कि चेस्ट फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और ईएनटी जैसे जरूरी विशेषज्ञों की तैनाती ही नहीं है। नतीजतन गंभीर मरीजों को मजबूरी में हायर सेंटर रेफर किया जाता है।रोजाना करीब 1000 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं। सुबह से ही लंबी कतारें लग जाती हैं। जांच और दवा वितरण में देरी आम बात हो चुकी है। सीएचसी–पीएचसी से रेफर होकर आए मरीजों को भी विशेषज्ञ न मिलने पर लौटना पड़ता है या लखनऊ जैसे शहरों का रुख करना पड़ता है। इससे गरीब मरीजों पर समय और पैसे का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। सूत्रों के अनुसार जनरल फिजिशियन के तीन पद स्वीकृत हैं, लेकिन केवल एक ही कार्यरत है। कई बार बाल रोग विशेषज्ञ को फिजिशियन की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। वहीं जनरल सर्जन की अनुपस्थिति में ऑर्थो सर्जन को जनरल सर्जरी के मरीज देखने पड़ते हैं।

इलाज की गुणवत्ता पर भी सवाल...

फिलहाल अस्पताल में तीन पैथोलॉजिस्ट, तीन आई सर्जन, तीन ऑर्थो सर्जन, एक फिजिशियन, एक रेडियोलॉजिस्ट, दो बाल रोग विशेषज्ञ, एक चर्म रोग विशेषज्ञ, दो एनेस्थेटिस्ट और दो जनरल सर्जन तैनात हैं। इतने कम संसाधनों में पूरे जिले का बोझ संभालना आसान नहीं है। मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि भीड़ बढ़ते ही व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। यह स्थिति उस अयोध्या के लिए शर्मनाक है, जो खुद को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है। इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय चौधरी ने बताया कि शासन से लगातार पत्राचार किया जा रहा है और जल्द ही चिकित्सकों की

तैनाती की उम्मीद है। सवाल यह है कि जब तक ये उम्मीदें हकीकत नहीं बनतीं, तब तक क्या रामनगरी के गरीब और ग्रामीण मरीज इसी तरह इलाज के लिए भटकते रहेंगे? आस्था के शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था की यह बदहाली अब प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है।

अयोध्या : जिला अस्पताल में लावारिस मरीज से अभद्रता !

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। जिला अस्पताल में एक लावारिस बीमार व्यक्ति से कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्वराज इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नही करता।बताया गया कि समाजसेवी व जिला पंचायत सदस्य प्रदीप यादव सड़क किनारे पड़े एक अज्ञात बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि इमरजेंसी में मौजूद फार्मासिस्ट और नर्स ने तत्काल इलाज शुरू करने के बजाय सवाल–जवाब करने शुरू कर दिए। वीडियो में कथित रूप से यह कहते सुना गया कि मरीज को दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं ले जाया गया। इलाज में देरी से नाराज समाजसेवी धरने पर बैठ गए। हंगामा और पुलिस हस्तक्षेप के बाद प्रशासन हरकत में आया, तब जाकर मरीज को भर्ती किया गया। मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

22 फरवरी को लगेगा मेगा विधिक सहायता शिविर

न्याय रथ को जिला जज ने दिखाई हरी झंडी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। शहर में 22 फरवरी (रविवार) को मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होगा, जहां आमजन को नि:शुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी और सुविधा प्रदान की जाएगी। शिविर के सफल संचालन और प्रचार–प्रसार के लिए मंगलवार दोपहर 2 बजे न्याय रथ को रवाना किया गया। जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा ने दीवानी न्यायालय परिसर से न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। न्याय रथ के माध्यम से लोगों को नि:शुल्क विधिक सहायता, केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा उनके लाभों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और न्यायिक सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है।अधिकारियों ने बताया कि अधिक से अधिक लोगों को शिविर से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि जरूरतमंदों को समय पर न्याय और सहायता मिल सके। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रजनी शुक्ला सहित कई न्यायिक अधिकारी सीजीएम सुधांशु शेखर उपाध्याय, एसीजीएम महेंद्र पासवान, बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका मिश्रा तथा बड़ी संख्या में अधिवक्ता भी उपस्थित रहे।

रामनगरी में संत असुरक्षित, प्रशासन पर उठे सवाल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या को देश–दुनिया आस्था, श्रद्धा और साधु–संतों की तपोभूमि के रूप में जानती है। लेकिन आज वही अयोध्या धीरे–धीरे जमीन के कारोबार और दबंगई की गिरफ्त में फंसती नजर आ रही है। श्रीराम मंदिर निर्माण के बाद बढ़ी लोकप्रियता और जमीनों की कीमतों ने यहां आस्था को मुनाफे का जरिया बना दिया है।

ताजा मामला कोतवाली क्षेत्र के स्फटिक शिला के पीछे स्थित सरयू नगर कॉलोनी का है, जहां 90 वर्षीय महात्मा राम रतन दास अपने ही मंदिर परिसर में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आरोप है कि कुछ लोग मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से जबरन घुस आए और वृद्ध संत को बाहर निकालने की कोशिश की। महात्मा के उत्तराधिकारी दामोदर दास के मुताबिक, आरोपी बिना किसी डर के मंदिर परिसर में घुसे, बच्चों को बाहर धकेला और पूरे परिसर में आतंक का माहौल बना दिया। यह घटना न केवल एक संत के सम्मान पर हमला है, बल्कि यह दर्शाती है कि अब भूमाफिया धार्मिक स्थलों तक को नहीं बख्श रहे।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद होने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि कई बार आवेदन देने के बाद भी मामला दर्ज नहीं किया गया। इससे पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

तिलोदकी गंगा को मिली नई पहचान

» कोका–कोला फैक्ट्री को एनजीटी की फटकार

अयोध्या। तिलोदकी गंगा से जुड़े मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान एडीएम एफआर अमित कुमार भट्ट, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता आर के गौतम और याचिकाकर्ता दुर्गा प्रसाद यादव एक साथ उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान तिलोदकी गंगा को आधिकारिक रूप से नदी मानते हुए उससे संबंधित सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं। कोर्ट ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं दूसरी ओर, अमृत बटलर स्थित कोका कोला फैक्ट्री को लेकर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने फैक्ट्री प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि तिलोदकी गंगा के बचे हुए

हिस्से का निर्माण और संरक्षण कार्य अप्रैल माह तक हर हाल में पूरा किया जाए। एनजीटी ने स्पष्ट किया कि तय समयसीमा के भीतर कार्य पूरा न होने की स्थिति में संबंधित इकाई के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई उम्मीद जगी है और स्थानीय लोगों ने भी कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है।

महाराष्ट्र में मुस्लिमों का 5% आरक्षण रद्द, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से विशेष कोटा खत्म

पूर्व गठबंधन सरकार का निर्णय पलटा, सामाजिक न्याय विभाग का नया शासनादेश लागू

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय को दिए जा रहे 5 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से जारी ताज़ा शासनादेश के अनुसार अब राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और अर्धसरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय के लिए कोई अलग आरक्षण लागू नहीं रहेगा। आदेश जारी होते ही संबंधित प्रमाणपत्र जारी करने और वैधता जांच की प्रक्रियाओं पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार यह निर्णय पूर्व गठबंधन सरकार के समय लागू आरक्षण नीति की समीक्षा के बाद लिया गया है। नई व्यवस्था में स्पष्ट किया गया है कि आगे से प्रवेश और भर्ती प्रक्रियाएं सामान्य आरक्षण ढांचे के तहत ही संचालित होंगी। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पुराने कोटे के आधार पर लंबित मामलों को भी आगे न बढ़ाया जाए और सभी संबंधित रिकॉर्ड अपडेट किए जाएं।

यह आरक्षण व्यवस्था वर्ष 2014 में तत्कालीन कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन सरकार के कार्यकाल में लागू की गई थी। उस समय मुस्लिम समुदाय को 5 प्रतिशत और मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। चुनाव से ठीक पहले लिए गए इस फैसले पर कानूनी विवाद भी खड़े हुए थे और बाद में सत्ता परिवर्तन के साथ इसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी। अब वर्तमान सरकार ने उस निर्णय को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया है।

फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। इम्तियाज जलील ने आदेश की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन से जूझ रहे समुदाय को राहत देने के बजाय सुविधा खत्म करना अनुचित है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता जलील ने कहा कि यह फैसला रमजान से पहले समुदाय को झटका देने जैसा है। उन्होंने दावा किया कि पहले न्यायिक टिप्पणियों में भी मुस्लिम समुदाय में ड्रॉपआउट दर अधिक होने की बात सामने आई थी, ऐसे में सहयोग की जरूरत थी, कटौती की नहीं।

उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे किसी भी परिस्थिति में अपनी पढ़ाई जारी रखें और कानूनी विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। वहीं सरकार की ओर से अभी विस्तृत राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विभागीय स्तर पर आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

- एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने फैसले को समुदाय के लिए बड़ा झटका बताया
- राज्य सरकार ने मुस्लिमों का 5त्न आरक्षण तत्काल प्रभाव से रद्द किया
- शिक्षा संस्थानों और सरकारी-अर्धसरकारी नौकरियों में विशेष कोटा समाप्त
- सामाजिक न्याय विभाग ने नया शासनादेश जारी किया
- आरक्षण आधारित प्रमाणपत्र और वैधता प्रक्रियाएं रोकी गईं
- वर्ष 2014 में पूर्व गठबंधन सरकार ने लागू किया था कोटा
- फैसले पर इम्तियाज जलील ने जताई कड़ी आपत्ति
- एआईएमआईएम ने निर्णय को समुदाय के लिए बड़ा झटका बताया
- छात्रों से पढ़ाई जारी रखने की अपील, कानूनी विकल्पों के संकेत

एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंचे फिनलैंड के पीएम और गूगल सीईओ पिचाई

डिजिटल-एआई साझेदारी पर फोकस

- फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो और सुंदर पिचाई की मौजूदगी से समिट को वैश्विक धार
- 20 फरवरी को कीनोट संबोधन देंगे पिचाई; वीआईपी मूवमेंट के चलते कड़े सुरक्षा प्रबंध

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर वैश्विक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई समिट में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस उच्चस्तरीय भागीदारी से भारत की डिजिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षा और सतत विकास क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

समिट का आयोजन 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया जा रहा है, जहां दुनिया भर के नीति-निर्माता, टेक उद्योग के दिग्गज, शोधकर्ता और स्टार्टअप प्रतिनिधि जुटे हैं। आयोजन को भारत के एआई विजन और डिजिटल नेतृत्व के प्रदर्शन के बड़े मंच के रूप में देखा जा रहा है।

फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के भारत आगमन पर कौशल विकास व उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि यह दौरा भारत और फिनलैंड के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को नई गति देगा। विशेष रूप से डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई, शिक्षा और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा।

टेक दिग्गज कंपनी गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई 20 फरवरी को समिट में मुख्य भाषण (कीनोट एड्रेस) देंगे। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत आकर खुशी हो रही है और हर बार की तरह गर्मजोशी से स्वागत मिला है। उनके संबोधन में एआई के जिम्मेदार उपयोग, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इकोसिस्टम पर फोकस रहने की संभावना है।

समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक बुधवार और गुरुवार को कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश और आवाजाही को लेकर आंशिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों को शाम 4:30 बजे तक कन्वेंशन एरिया खाली करना होगा। शाम 6 बजे के बाद प्रधानमंत्री द्वारा राज्य अतिथियों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए रात्रिभोज की मेजबानी प्रस्तावित है, जिसके चलते विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू रहेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक प्रतिनिधियों और आगंतुकों के भारी उत्साह को देखते हुए एआई एक्सपो क्षेत्र 18 फरवरी तक रात 8 बजे तक खुला रखा जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि सुरक्षा और वीआईपी कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए समय और प्रवेश से जुड़ी व्यवस्थाएं पहले से तय की गई हैं ताकि आयोजन सुचारू रूप से संचालित हो।

प्रधानमंत्री ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि भारत का सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर सेवाओं के निर्यात की रीढ़ रहा है और एआई के दौर में यह आर्थिक विकास का और बड़ा इंजन बनने जा रहा है। सरकार की रणनीति एआई को नवाचार, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जोड़ने पर केंद्रित है।

- इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16-20 फरवरी तक नई दिल्ली में
- फिनलैंड के पीएम पेटेरी ओर्पो और गूगल सीईओ सुंदर पिचाई पहुंचे
- 20 फरवरी को सुंदर पिचाई का कीनोट एड्रेस प्रस्तावित
- भारत-फिनलैंड के बीच डिजिटल, एआई, शिक्षा व सतत विकास सहयोग पर जोर
- भारत मंडपम में वीआईपी मूवमेंट के चलते कड़े सुरक्षा प्रबंध
- डेलिगेट्स के लिए समयबद्ध प्रवेश और निकासी व्यवस्था लागू
- एआई एक्सपो क्षेत्र बढ़े समय तक खुला रखने का निर्णय

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें https://epaper.swarajindianews.com